(घ) इन संस्थानों के माध्यम से इस देश में कितनी विदेशी मुद्रा वर्षवार आ रही है और इन कार्यालयों द्वारा किस प्रकार का काम किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) और (ख) विदेशी कम्पनियों के सम्पर्क कार्यालयों को भारतीय निर्यात के संवर्धन के अभियान में सहयोग देने की अनुमति प्रदान करने का फैसला कर लिया गया है । इस व्यवस्था की मुख्य बातें ये हैं :—

(1) ये कार्यालय घरेलू व्यापार में हिस्सा नहीं लेंगे ।

(2) वे आयातकर्ताओं की ओर से भारतीय कम्पनियों को निर्यात के आर्डर दे सकेंगे और वस्तुओं के चयन और उनकी विशेषता और उनके डिजाइन का अनुमोदन करने, निर्यात के लिए नमूने प्राप्त करने और वस्तुओं आदि के लदान की ठीक समय पर व्यवस्था करने जैसे संबंधित कार्य भी कर सकेंगे ।

(3) वस्तुओं का वास्तविक निर्यात भारतीय कम्पनियों के द्वारा किया जाएगा ।

(4) जैसा अब तक होता रहा है, इन सम्पर्क कार्यालयों के समस्त व्यय को विदेशों से प्राप्त प्रेषणाओं में से पूरा किया जाएगा ।

(ग) और (घ) उपर्युक्त सुविधा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 दिसम्बर, 1988 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके घोषणा की थी । इसलिए इतनी जल्दी ऐसी जानकारी इकट्ठी करने से कोई लाभ नहीं होगा ।

Value of Rupee

1111. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what was the real value of a rupee during the last three years; and

(b) what steps Government are taking to prevent this actual devaluation trend of rupee?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) The value of rupee calculated as the reciprocal of the Consumer Price Index for Industrial Workers at base: 1960-100 works out to 12.22 paise for the month of December, 1988 (the latest available). The comparable figures for December, 1987 and 1986 were 13.30 paise and 14.53 paise respectively.

The decline in the value of rupee is on account of increase in prices. However, the rise in prices has not adversely affected the well-being of the common man, whose nominal income has gone up even faster during the period. The Government have adopted a package of measures to contain the rise in prices. These measures include supply of essential commodities through the public distribution system, augmenting domestic supplies of essential commodities through imports as necessary, exercising strict monetary and fiscal discipline, action against hoarders and blackmarketeers and close monitoring of prices of essential commodities.